जनसत्ता

25 जून, 2019

सहिष्णुता का पैमाना

सामाजिक विविधता की कसौटी पर देखें तो भारत दुनिया के उन गिने-चुने देशों में है जहां अलग-अलग धर्मों और मतों को मानने वाले समूहों या समुदायों को पूरी आजादी है। देश का संविधान यहां के सभी नागरिकों को अपनी आस्था के निर्वाह का अधिकार और गारंटी देता है। इसके बावजूद अगर अमेरिका के विदेश विभाग की ओर से जारी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में भारत के कुछ खास समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता के बाधित होने का दावा किया गया है तो उस पर सवाल उठने लाजिमी हैं। हालांकि यह एक कड़वी सच्चाई है कि देश के अलग-अलग हिस्सों से अराजकता और हिंसा की कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिनसे ऐसा लगता है कि धर्म के आधार पर कुछ चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। मगर यह भी सच है कि इस तरह की किसी भी घटना के बाद कानून अपना काम करता है, दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। लेकिन कुछ असामाजिक और अराजक तत्त्वों की गैरकानूनी हरकतों को देश में मौजूद धार्मिक स्वतंत्रता के पूरी तरह बाधित होने के रूप में नहीं देखा जा सकता।

स्वाभाविक ही भारत ने अमेरिका की ओर से जारी इस रिपोर्ट को खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और बहुलतावादी समाज वाला देश है जो लंबे समय से सहिष्णुता और समावेश के लिए प्रतिबद्ध है; भारत का संविधान सभी नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, जिनमें अल्पसंख्यक भी शामिल हैं। जाहिर है, एक ओर संविधान में अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी व्यवस्था की गई है तो दूसरी ओर सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से उन अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जाते हैं। सही है कि भारत भौगोलिक रूप से एक बड़ा विविध पहचानों वाला देश है और कई बार यहां कुछ ऐसी अफसोसजनक घटनाएं होती रहती हैं, जिनके पीछे धार्मिक कट्टरता से जुड़ी सोच या व्यवहार मुख्य रूप से जवाबदेह होते हैं। लेकिन इनके आधार पर समूचे देश को एक ही नजर से देख लेना और इसे भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर खतरे के रूप में पेश करना अतिरेक ही माना जाना चाहिए। फिर भी, ऐसी रिपोर्टें आगाह करती हैं कि अगर कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिनसे देश की नकारात्मक छवि बनती है तो उन पर भी पूरी तरह काबू पाया जाए।

हालांकि यह भी सच है कि पिछले कुछ सालों के दौरान असामाजिक तत्त्वों ने एक भीड़ के रूप में गाय की रक्षा के नाम पर एक धर्म-विशेष की पहचान से जुड़े लोगों पर हमले किए, कइयों को पीट-पीट कर मार डाला। ऐसे मामले अब भी सामने आते हैं, जिनमें भीड़ ने किसी अल्पसंख्यक को उसके धर्म से इतर कुछ खास धार्मिक नारे लगाने को मजबूर किया और उसे सार्वजनिक रूप से बुरी तरह मारा-पीटा। इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस और प्रशासन ने ऐसे मौकों पर कानूनी कार्रवाई की, लेकिन अब भी ऐसी घटनाएं पूरी तरह रोकी नहीं जा सकी हैं। यह कोई छिपी बात नहीं है कि कई नेता अक्सर बेवजह भड़काऊ भाषण देते हैं। जरूरत इस बात की है कि राजनीतिक स्तर पर देश में बने उन्माद के माहौल को काबू में किया जाए। किसी भी स्थिति में भीड़ को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर इस प्रवृत्ति पर सख्ती से रोक नहीं लगाई गई तो संविधान में दर्ज अधिकार और सरकार की ओर से सभी धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार के दावों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा।

अपराध और सवाल

राजधानी दिल्ली में पिछले चार दिन में जिस तरह हत्या की ताबड़तोड़ तीन बड़ी वारदातें हुई हैं, वे दहलाने वाली हैं। इन वारदातों ने लोगों, खासतौर से बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लगता है, दिल्ली में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है और अपराधी बेखौफ होकर अपना काम कर रहे हैं। सड़क पर सरेआम गोलियां चलाने से लेकर रोडरेज जैसी घटनाओं हों या छोटी-छोटी बातों पर जान ले लेनी की घटनाएं, आपराधिक तत्वों के भीतर पुलिस और कानून का कोई भय खत्म हो गया है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? खासतौर से बुजुर्गों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी? हाल में वसंत विहार इलाके में एक बुजुर्ग दंपति और उनके यहां काम करने वाली सहायिका की गला रेत कर हत्या कर दी गई। इससे पहले एक शिक्षक और उनकी पत्नी को चाकुओं से गोद कर मार दिया गया था। एक व्यक्ति ने अपने तीन बच्चों और पत्नी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया और फिर खुद ने भी जान देने की कोशिश की, लेकिन बच गया। इस तरह की घटनाएं दिल्ली जैसे महानगर का वीभत्स चेहरा है। यह सरकार, पुलिस और समाज तीनों के लिए गंभीर चुनौती है।

दिल्ली में ऐसे बुजुर्गों की संख्या काफी है जो अकेले रह रहे हैं। इनकी देखभाल की सबसे पहली जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस की होती है। बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने बाकायदा अपना एक तंत्र भी बनाया हुआ है। लेकिन ऐसा तंत्र किस काम का जो सुरक्षा न दे पाए और जब कत्ल हो जाए तो इधर-उधर की खाक छानता रहे! जाहिर है, अपराधी ज्यादा शातिर साबित हो रहे हैं और पुलिस के प्रयास उनके सामने बौने पड़ रहे हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि पहले के मुकाबले बुजुर्गों की सुरक्षा की दिशा में पुलिस ने कुछ प्रयास तो शुरू किए हैं। बीट कांस्टेबल, थानाध्यक्ष, सहायक पुलिस आयुक्त जैसे अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं, अकेले रह रहे बुजुर्गों का पंजीकरण कर बड़ा डाटाबेस तैयार किया गया है, बुजुर्गों की मदद के लिए ऐप भी बनाया गया है, हेल्पलाइन नंबर भी है। लेकिन अगर हम बुजुर्गों को सुरक्षा दे ही नहीं पा रहे तो फिर ये सारी कवायदें बेकार हैं। हकीकत तो यह है कि पुलिस को जिस तरह इस संवेदनशील मसले पर ध्यान देना चाहिए, वह नहीं देती। काम के दबाव का बहाना बना दिया जाता है। समस्या यह है जब अपराधी वारदात को अंजाम दे जाते हैं उसके बाद ही सारा तंत्र हरकत में आता है।

दूसरी बड़ी बात यह है कि ज्यादातर रिहायशी इलाकों और हाउसिंग सोसायटियों में सुरक्षा के बंदोबस्त पुख्ता नहीं है। जिस वसंत अपार्टमेंट में बुजुर्ग दंपति की हत्या हुई, उसकी सुरक्षा संबंधी खामियां अब सामने आ रही हैं। यह हाल ज्यादातर सोसायटियों का है। आपराधिक तत्व इसका भरपूर फायदा उठाते हैं। हालांकि अब कई जगह सीसीटीवी कैमरे लगने से अपराधियों तक पहुंचना पुलिस के लिए आसान तो गया है और कई हत्याओं के मामले सुलझे भी हैं। दिल्ली में ज्यादातर परिवार ऐसे हैं जिनमें बुजुर्ग अलग रह रहे हैं और उनके बच्चे अपने परिवारों के साथ अलग। कइयों के बच्चे विदेश में रहते हैं। ऐसे में बुजुर्गों की सुरक्षा सोसायटी के गार्डों, स्थानीय पुलिस आदि पर ही निर्भर है। समस्या यह है कि जैसा मजबूत निगरानी तंत्र होना चाहिए, वह है नहीं। इसीलिए अपराधी बेलगाम हैं!

कल्पमेधा

बातचीत प्रिय हो, पर ओछी न हो। चुहल हो, बनावट हो, मुक्त हो, पर अश्लील न हो। विद्वतापूर्ण हो, पर घमंडयुक्त न हो। अनोखी हो, पर झूठ न हो।

– शेक्सपियर

मानसून की पहेली और संकट

सुविज्ञा जैन

प्राकृतिक रूप से मानसून 19 जून तक देश के दो तिहाई हिस्से तक पहुंच जाता था। इस बार उस समय तक यह सिर्फ बारह फीसद क्षेत्र को ही कवर कर पाया। बारह फीसद का यह इलाका इतना छोटा है कि मानसून आने के दरवाजे यानी केरल और उसके नजदीकी इलाकों तक ही सिमट जाता है। जाहिर है, कृषि प्रधान देश में किसानों के लिए एक भयावह स्थिति है।

मानसून की गड़बड़ी इतना छोटा संकट नहीं है। चाहे मौसम विज्ञान के वैज्ञानिक हों, चाहे मीडिया, किसी की भी तरफ से उतनी चिंता जताई जाती नहीं दिख रही। आसन्न संकट के अंदेशे न जताए जाने का एक मतलब यह है कि किसी आपदा से निपटने की तैयारी शुरू न होना। बरिश को लेकर अब तक की भविष्यवाणियों की बड़ी फजीहत हो चुकी है। मौसम वैज्ञानिक बता रहे थे कि इस बार मानसून समय पर आएगा। लेकिन मानसून ने एक-दो दिन नहीं, बल्कि पूरे सात दिन देर से दस्तक दी। देर से दस्तक के बाद एक और अड़चन आ गई। मानसून जिस रफ्तार से पूरे देश तक पहुंचता था, वह रफ्तार इस बार एकदम रूक-सी गई है। इसी तरह पहले बताया जा रहा था कि वायु नाम का चक्रवात मानसून की प्रणाली को गड़बड़ा सकता है। लेकिन चक्रवात तट को छुए बगैर ही गुजर गया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस चक्रवात ने वातावरण की नमी सोख ली। इसी तरह मानसून को आगे बढ़ने में दिक्कत आने के भी नए कारण ढूंढ़े जा रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस युग में कम से कम छोटी अवधि के पूर्वानुमान तो इतने नहीं गड़बड़ाने चाहिए।

बहरहाल नई सूचना यह है कि मानसून कछुए की चाल से बढ़ रहा है, सो इस बार पूरे देश में मानसून फैलने में तीन से चार हफ्ते का समय और लग सकता है। इस देरी के क्या-क्या असर होंगे? और अनागत की जो आशंकाएं हैं, उनसे निपटने के लिए क्या तैयारियां सोची जा रही हैं? इक्का-दुक्का मीडिया रिपोर्ट के अलावा ये सारी बातें विशेषज्ञ चेतावनियों और खबरों से लगभग गायब हैं। यह बात दो महीने पहले कही गई थी कि इस बार अल निनो सक्रिय है। अल निनो यानी समुद्र में एक निश्चित क्षेत्र का पानी गर्म होना। इसके बारे में वैज्ञानिक तथ्य यह है कि अन निनो के सक्रिय होने वाले साल में भारत में बारिश कम होती है। लेकिन इस साल यह पता होने के बाद भी हाल के इस पूर्वानुमान को भी खारिज कर दिया गया था और कहा गया था कि जून में अगर अल निनो का असर हुआ भी तो वह जुलाई या आगे के दो महीनों में खत्म हो जाएगा। जून के बाईस दिन गुजरने के बाद भी मानसून फैलने का जो कुदरती अंदाज है, वह बता रहा है कि आफत बड़ी भी आ सकती है। गौरतलब है कि सरकारी मौसम विभाग इस समय जो आंकड़े पेश कर रहा है, वे एक बड़े अंदेशे का इशारा कर रहे हैं।

प्राकृतिक रूप से मानसून 19 जून तक देश के दो तिहाई हिस्से तक पहुंच जाता था। इस बार उस समय तक यह सिर्फ बारह फीसद क्षेत्र को ही कवर कर पाया। बारह फीसद का यह इलाका इतना छोटा है कि मानसून आने के दरवाजे यानी केरल और उसके नजदीकी इलाकों तक ही सिमट जाता है। जाहिर है, कृषि प्रधान देश में किसानों के लिए एक भयावह स्थिति है। खासतौर पर उस देश में जहां आधी से ज्यादा खेती बारिश के सहारे ही होती है। वैसे जहां सिंचाई की व्यवस्था भी है, वहां भी हालत कम बुरी नहीं है। उत्तर भारत के कुछ इलाके छोड़ कर देश के लगभग सभी बांधों में पानी लगभग खत्म ही है। यानी मानसून की और ज्यादा गड़बड़ी कुछ ज्यादा ही बड़ी आफत पैदा कर सकती है। लेकिन सरकारी विभागों की तरफ से अभी भी बारिश का नया पूर्वानुमान जारी नहीं हुआ है।

यह भी एक तथ्य है कि मानसून का तय समय शुरू हुए अभी बाईस दिन ही गुजरे हैं। हो सकता है कि बाकी सवा तीन महीने में अच्छी बारिश हो जाए और देश में इस साल बारिश का आंकड़ा सामान्य बारिश के आसपास पहुंच जाए। लेकिन यह स्थिति पानी की भारी कमी यानी सूखे से भी ज्यादा विकट स्थिति पैदा कर सकती है। अगर सरकारी भविष्यवाणियों के मुताबिक चार महीने में गिरने वाला कुल पानी तीन महीने में गिर गया तो देश में कई जगह बाढ़ की विभीषिका तय मानिए।

वैसे देश को पिछले कुछ साल से नया अनुभव होने लगा है कि देश में सामान्य बारिश होने के बाद भी आधा देश सूखे की चपेट में आ जाता है। पिछले साल यही हुआ था। इतना ही नहीं, कम बारिश होने के बाद भी कई जगह बाढ़ से तबाही

हम नहीं रोक पा रहे हैं। हो सकता है कि मौसम वैज्ञानिकों और सामान्य प्रशासकों के लिए यह उतनी बड़ी बात न हो, लेकिन प्रबंधन प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञों और नीतिकारों के लिए इससे ज्यादा शर्म की क्या बात होगी? बहरहाल, इस समय आसार ये हैं कि यह साल पृथ्वी विज्ञान के विद्वानों, खासतौर पर मौसम वैज्ञानिकों और देश के जल वैज्ञानिकों के सामने कई सवाल खड़े कर सकता है। वैसे उनके पास एक ही जवाब होगा कि क्या करें, प्रकृति के खेल में हम दर्शकभर हैं।

फिलहाल सवाल पूर्वानुमानों की गड़बड़ी का भी उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है। अगर सही और सटीक भविष्यवाणियां हो भी जाएं तो चिंता जताने के अलावा क्या कर लेंगे? लेकिन नहीं। ये चिंताएं बड़े काम की होती हैं। ये चिंताएं ही हमें चिंताशील बनाती हैं। अपनी वर्तमान और अनागत समस्याओं के समाधान खोजने के लिए मौका बनाती हैं। इसीलिए वैज्ञानिकों और विद्वानों की जिम्मेदारी है कि वे हमें चिंता बताते चलें। किसी आसन्न संकट को हल्का करके न बताएं। मसलन, इस बार अल निनो के असर, मानसून आने में देरी और मानसून में ठहराव के पूर्वानुमानों को बताने में वैज्ञानिक शोधों की कमी हो सकती है। लेकिन जिस तरह से मानसून पूर्व की बारिश की कमी के आंकड़ों पर चिंता नहीं जाताई गई, उसका कोई तर्क नहीं हो सकता। बल्कि होता यह रहा है कि चारों तरफ पानी को लेकर मचे हाहाकार के बीच भी यही दावे किए जाते रहे कि हमारे बांधों में पर्याप्त पानी है। मीडिया भी हर साल की तरह शहरों में घड़े, बाल्टी और टैंकरों की समस्या बताता रहा। अगर बांधों में पर्याप्त पानी जैसे दावों की पड़ताल होगी तो यही पता चलेगा कि यह दावा इस आधार पर किया गया कि पिछले साल इन दिनों इतना ही पानी बांधों में बचा था। यह बात नहीं बताई गई कि पिछले साल भी ऐसा ही संकट था। पिछले साल ही नहीं, बल्कि पिछले कई साल से देश में बारिश के पानी के भंडारण की क्षमता जहां की तहां है। जबकि बढ़ती आबादी और उद्योग के लिए पानी की जरूरत बढ़ती ही जा रही है। पांच साल पुरानी जल भंडारण क्षमता को हम यह नहीं मान सकते कि आज वह सामान्य है। जरूरत साल दर साल जल भंडारण क्षमता बढ़ाने की थी।

इस बार मानसून के संकट के साथ एक सकारात्मक बात जरूर है। वह यह कि इत्तेफाक से देश में मानसून सत्र के दौरान ही पानी को लेकर हाहाकार मचा है। चाहे वह सूखे को लेकर हो या फिर बाढ़ को लेकर। जाहिर है, संसद के इस सत्र में जल प्रबंधन और जल परियोजनाओं खासकर जल भंडारण यानी बांधों और जलाशयों की बात जरूर होगी। बजट में पानी जैसी प्राथमिक जरूरतों पर प्रावधानों की बात जरूर आएगी। चूंकि किसानों और खेती की बात हर बजट में करनी ही पड़ती है, सो इस बार वह होगी ही। स्वाभाविक है कि आसन्न संकट के कारण जल प्रबंधन पर विशेष बजटीय प्रावधान जरूर सोच लिए गए होंगे। यानी इस बार वित्तमंत्री के बजट भाषण में देश के चिंतनीय जल प्रबंधन पर कुछ नया जरूर होना चाहिए।

सामूहिकता का संदेश

निशा नाग

दुनिया मेरे आगे

गली-कूचों और मुहल्लों वाले शहरों में मंदिरों की अच्छी-खासी तादाद देखी जाती है और अब नई बसी सोसाइटियों में भी एक न एक मंदिर जरूर होता है। वहां से अक्सर किसी खास त्योहार या मंगलवार, शनिवार या नवरात्र के मौके पर ताल-बेताल ढोलकी के साथ चम्मच की खट-खट की ऊंची आवाज के साथ गाए जाने वाले भजनों की पुकार कानों में पड़ती रहती है। उसे सुन कर अक्सर कुछ लोग मुंह बिचका कर और युवा गृहिणियां इसकी खाली बैठी औरतों का शगल कह कर खिल्ली उड़ाती हैं। पर सच यह है कि इस तरह की कीर्तन मंडली दरअसल चौपाल और किटी-पार्टी की तरह ही सामुदायिक मिलन का एक अवसर है। खासतौर पर उन महिलाओं के लिए, जो कुछ सुकून में हैं, जिन्होंने घर-परिवार की जिम्मेदारियों को निभा लिया है और शायद अब उनकी जरूरत घर में उतनी नहीं रही या सारी जिंदगी खटने के बाद अब वे अपने ढंग से जिंदगी का सुख लेना चाहती हैं। ठीक उसी तरह, जैसे लोक गीतों में लोक का हृदय बोलता है। कीर्तन मंडली के भजनों में प्रौढ़ महिला हृदय का अच्छा-खासा 'कैथार्सिस' होता है। इन कीर्तनों का समय भी अवसर के मुताबिक ही रखा जाता है। यानी इसमें हिस्सा लेने वालों के कामकाज और सुविधा को ध्यान में रख कर ही वक्त तय किया जाता है।

कीर्तन का आयोजन करवाने के कई कारण हो सकते हैं। मसलन, मन्नत पूरी होने या नौकरी लगने की दलील पर या फिर जन्मदिन या घर पर होने वाली किसी शादी से पहले भी लोग कीर्तन कराते हैं। कीर्तनों में कुछ भजन देवी-देवताओं की स्तुति के होते हैं तो कुछ अवसर के मुताबिक बना लिए जाते हैं। कुछ गंभीर किस्म के भजन होते हैं तो कुछ चुहल भरे भी। जैसे 'चले आना ऊंची अटारी मेरे बांके बिहारी'। फिल्मी तर्जों के साथ-साथ कुछ परंपरागत तो कुछ स्वरचित लयों पर ये भजन गाए जाते हैं। सुर सही होने की परवाह किसी को नहीं होती। जैसे मन करता है, उसी अंदाज में गाए जाते हैं, जिन्हें देख कर अब्दुल रहमान के 'संदेश रासक' का वह कथन याद आ जाता है- 'कोयल यदि मधुर स्वर में गाती है तो क्या कौवे न करकराएं, राजदरबार नें नर्तकी शास्त्रीय नृत्य करती है तो क्या ग्राम्य युवती न नाचे'!

यह परंपरा कब से चली आ रही है, इसका पता नहीं। सगुण भक्ति से लेकर निर्गुनिया संत, सभी की आराधना का प्रमुख माध्यम कीर्तन रहा है। गुरबानी के पाठ से लेकर बौद्ध धर्म के सामूहिक 'ओं मणि पद्में हूं' का पाठ इसी का एक रूप रहा है। एक अलग अंदाज और संदर्भ के साथ नात और कव्वाली तथा मुहर्रमों की मजलिस को भी देखा जा सकता है। हालांकि उसका संदर्भ बिल्कुल अलग हो जाता है, पर महिलाओं के इस तरह के खुलेपन के साथ चुहलबाजी और मन के रंजन का भाव इन्हीं साप्ताहिक कीर्तनों में रहता है।

इतिहास गवाह है कि अंग्रेजों द्वारा डेढ़ सौ साल पहले जिन गिरमिटिया मजदूरों को मारिशस-ट्रिनिडाड या फिजी भेजा गया था, वहां सोना कमाने के लालच में गए अमानवीय स्थितियों में जीते मजदूरों को जीने का संबल कीर्तन से ही मिलता था। कीर्तन के इस संदर्भ में महादेवी वर्मा का लिखा एक संस्मरण 'ठकुरी बाबा' याद आ रहा है, जहां वे कल्पवास करने गंगा किनारे जाती हैं और असमय रात को बारिश आ जाने से ग्रामीणों का एक दल उनकी कुटिया में घुस जाता है। तब महादेवी के आतिथ्य से प्रभावित होकर वह वहीं टिक जाता है। वह ग्रामीण दल जिस रूप में कीर्तन और सत्संग करता है, उसका निश्छल रूप महादेवी को भीतर तक छू लेता है। वे लिखती हैं- 'कबीर, सूर, तुलसी जैसे महान कवियों से लेकर अज्ञातनामा ग्रामीण तुक्कड़ों तक के पद उन्हें स्मरण थे। एक जो कड़ी गाता था, उसे सबका समवेत स्वर दोहरा देता था।' महादेवी कवि सम्मेलनों को दंगल (जहां सब लोग एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं) तो ग्रामीण दल के कीर्तन को हिंडोला कहती हैं, जिसमें 'ऊंचाई-निचाई का स्पर्श भी एक आत्म विस्मृति में विश्राम देता है'।

आजकल इस सत्संगनुमा कीर्तन में अच्छा-खासा ग्लैमर भी शामिल हो गया है, जहां लुभावने चेहरों वाली तथाकथित संत महिलाएं विशेष भाव-भंगिमा के साथ कभी-कभी फिल्मी गानों की तर्ज पर भजन गाती हुई दिखती हैं। व्यावसायिकता भी इनका हिस्सा हो गई है। जागरण करवाने और घरों में कीर्तन करवाने वाली व्यवसायिक मंडलियां भी हैं जो अच्छा-खासा पैसा लेकर यह काम करती हैं, लेकिन महिलाओं द्वारा किए जाने वाले इस कीर्तन का अंदाज ही निराला है, जहां गली-मुहल्ले की बातचीत, चुहलबाजी और थोड़ी-बहुत आपसी राजनीति और नाराजगी भी शामिल रहती है। जैसे अगर किसी महिला की किसी अन्य महिला से कोई नाराजगी है तो यह तय है कि वह उसके द्वारा गाए जाने भजन में वह अपना स्वर नहीं मिलाएगी! पर सच तो यह है कि ये कीर्तन वाचिक परंपरा में समुदाय को रससिक्त करने और सामूहिकता में जीने का संदेश देते हैं।

चौपाल

किसान का संकट

किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब सभी किसानों को सालाना छह हजार रुपए मिलेंगे। साथ ही, किसानों के लिए पेंशन योजना का एलान भी किया गया है। लेकिन क्या इससे किसानों की हालत सुधर पाएगी? कृषि संकट का समाधान, किसानों की पैदावार और उनके आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना सरकार के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। यह संकट इतना विकराल रूप धारण कर चुका है कि उसमें सुधार के लिए सरकार को तुरंत उपाय सोचने होंगे। नीति आयोग के अनुसार पिछले दो साल में किसानों की आय में वास्तविक बढ़ोतरी लगभग शून्य हुई है और उसके पिछले पांच सालों में हर साल आधा प्रतिशत से भी कम बढ़ोतरी हुई। यानी, सात सालों से किसानों की आय में वृद्धि न के बराबर हुई है।

ऑर्गनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 2000-2017 के बीच में किसानों को फसलों का समुचित मूल्य नहीं मिलने से पैंतालीस लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2016 के आर्थिक सर्वे में किसान परिवार की सत्रह राज्यों में आय बीस हजार रुपए सालाना से कम है, यानी 1700 रुपए मासिक या लगभग पचास रुपए रोजाना। सवाल है कि इस आय में कोई परिवार कैसे पलता होगा? खेती में पैसा नहीं है, उसके मजदूरों के पास काम नहीं है। इसके अलावा, मंडी हो, उत्पादन हो या पीएम फसल योजना में मुआवजा ही लेना हो, किसानों को हर कदम पर दिक्कतें आती हैं। किसानों की ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी तो वे काफी हद तक आर्थिक संकट से उबर सकते हैं। कुल मिला कर कृषि में सुधार का रास्ता गांव के रास्ते ही जाएगा।

● *संजीव कुमार, सहारनपुर*

तीन तलाक और विपक्ष

सरकार ने तीन तलाक की प्रथा खत्म करने के लिए जो पहल की है, वह बहुत ही सोच-समझ कर महिलाओं और बच्चों के हित में उठाया गया कदम है। इसका विरोध करने वालों को सोचना चाहिए कि आखिर क्यों नहीं वे इस दकियानूसी परंपरा को खत्म नहीं करना चाहते? क्यों वे अपने राजनीतिक और स्वयं के स्वार्थ के लिए एक बेहतर पहल का विरोध कर रहे हैं? देखा जाए तो तीन तलाक बहुत-सी सामाजिक बुराइयों को ही दूर करेगा, जिसमें घर की बर्बादी, महिलाओं की परेशानी, बच्चों की तकलीफें और इससे उपजी अन्य अनैतिक बुराइयां खत्म होंगी। मात्र विरोध करना ही नहीं, बल्कि गहरी सोच भी होनी चाहिए विरोध करने वालों की कि हम शासन-प्रशासन में रह कर किस तरह सामाजिक बुराइयों को दूर करने में और लोगों के हित के लिए कितना और क्या कर सकते हैं। तभी हम बेहतर समाज सुधारक बन सकते हैं। विवेकहीन राजनीति करने से न तो खुद, न पार्टी, न ही समाज और देश का भला होने वाला है।

● *शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर*

जल संकट और सबक

चेन्नई आजकल गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। इस जल संकट ने लोगों को भारी मुश्किल में डाल दिया है। यहां बारिश न होने के कारण जल के प्राकृतिक स्रोत भी सूख गए हैं, इस कारण यहां जल संकट और गहराता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ नीति आयोग की रिपोर्ट ने जो यह रिपोर्ट जारी की है कि हमारे देश में 2030 तक चालीस फीसद आबादी के पास पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं होगा, काफी चिंताजनक है। चेन्नई में बेशक आजकल जल संकट चल रहा है, लेकिन देश के बहुत से और राज्य भी ऐसे संकट का सामना कर रहे हैं। इन राज्यों का भूजल स्तर गिरता जा रहा है। मोदी सरकार ने 2024 तक देश के हर घर तक नल से जल की योजना का लक्ष्य निर्धारित किया है।

अगर बारिश के कम होने के कारणों पर ध्यान नहीं दिया, पानी को संभालने, नदियों को गंदा करने से बाज नहीं आए और भूजल के गिरते स्तर को रोकने के लिए सरकारों और आमजन ने गंभीरता नहीं दिखाई तो वह दिन दूर नहीं जब देश का हर शहर और हर गांव पीने वाले साफ पानी की एक-एक बूंद को तरसने लगेगा। ऐसे में देश के हर घर में नल तो सरकार पहुंचा भी देगी, लेकिन नल में जल नहीं होगा। यहां यह भी कहना उचित होगा कि जब देश में सूखे की स्थिति पैदा होती है तब पानी को बचाने के उपाय और तौर तरीकों की बात सरकारें, प्रशासन और लोग करने लगते हैं। लेकिन जब गर्मी का मौसम चला जाता है तो सभी अगली गर्मी के मौसम और सूखा पड़ने तक लंबी तान के सो जाते है। अगर आने वाली पीढ़ी के लिए साफ पानी बचा कर रखना है तो सबको मन में एक प्रण लेना होगा कि हर हाल में पानी बचाना है।

● *राजेश कुमार चौहान, जालंधर*

युद्ध का खतरा

अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जिस तरह के युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं उससे कई देशों की आर्थिक स्थिति संकट में पड़ सकती है। अमेरिका ने ईरान पर साइबर हमला कर उसके राकेट और मिसाइल लांचर वाले कंप्यूटर को जाम करने का दावा किया है, वहीं ईरान भी इसके घातक नतीजों की धमकी दे रहा है। युद्ध से अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में अस्थिरता का माहौल बन रहा है और तेल के दाम बढ़ सकते हैं। अगर दोनों देशों में युद्ध हुआ तो यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिकूल होगा।

● *विविधा, डीएसजे, दिल्ली विवि*

दक्षिण अफ्रीका का संकट

पिछली आठ मई को दक्षिण अफ्रीका में हुए चुनाव के नतीजे में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस को अट्ठावन फीसद मतों के साथ जीत हासिल हुई थी। तब लगा था कि देश में सब कुछ ठीक-ठाक होगा, लोग खुश होंगे, अर्थव्यवस्था सुधरेगी, जीडीपी बढ़ेगी, बेरोजगारी कम होगी। मगर ये क्या अचानक वहां के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा का इकबालिया बयान आ गया। उन्होंने कहा, देश का माली हालत ठीक नहीं है। देश पर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों का कर्ज बढ़ता जा रहा है। बेरोजगारी सत्ताईस फीसद पर है और युवाओं में ये प्रतिशत पचास के ऊपर चला गया है। इसका मतलब देश इस समय डूबने के कागार पर है। सवाल है कि रंगभेद से तो मुक्ति मिल गई, मगर गुरबत से देश कब मुक्त होगा?

● *जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com